

## यूरोपीय संघ ने लगाए बेलारूस पर प्रतिबंध

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय संघ (EU) ने बेलारूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें उसकी एयरलाइन्स को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र और हवाई अड्डों का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया।



### प्रमुख बद्धि:

#### बेलारूस की राजनीतिक पृष्ठभूमि:

- यूरोप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के कारण उत्पन्न हुई अराजकता के बीच वर्ष 1994 में पदभार ग्रहण किया।
- इन्हें प्रायः यूरोप के "अंतिम तानाशाह" के रूप में वर्णित किया जाता है, उन्होंने सोवियत साम्यवाद के तत्त्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया है।
  - वह 26 वर्षों से सत्ता में हैं तथा अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा राज्य के हाथों में है और वसिधियों के खिलाफ सेंसरशिप एवं पुलिस कार्रवाई का उपयोग कर रहे हैं।
- वर्ष 2020 में लुकाशेंको को चुनावों में वजिता घोषित किये जाने के बाद राजधानी मनिस्क में वसिध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो हसिक सुरक्षा कार्रवाई के कारण हुए थे।
  - बेलारूस में स्थिर अर्थव्यवस्था और चुनाव की नषिपक्षता पर संदेह को लेकर सरकार के खिलाफ व्यापक गुस्सा व्याप्त है।

#### पछिले प्रतिबंध:

- हसिक कार्रवाई के जवाब में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2020 में बेलारूस के खिलाफ कई दौर के वित्तीय प्रतिबंध लगाए।

- अमेरिका ने नौ राज्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं और राष्ट्रपतलिकाओंको सहति 16 व्यक्तियों पर यात्रा प्रतर्बिध और लक्ष्मि वत्तित्तीय प्रतर्बिध भी लगाए । ये प्रतर्बिध पहली बार वर्ष 2006 में लगाए गए थे तथा वर्ष 2008 में इन्हें और अधकि सख्त कर दया गया ।
- कई वर्ष पहले दो वपिक्षी राजनेताओं, एक पत्रकार और एक व्यापारी के लापता होने के बाद यूरोपीय संघ ने पहली बार वर्ष 2004 में बेलायूस के खलाफ प्रतर्बिधात्मक उपाय प्रस्तुत कये थे ।

### हालया प्रतर्बिधों का कारण:

- बेलायूस के राष्ट्रपतनि एक यात्री जेट को ज़बरन रोककर और एक वपिक्षी पत्रकार को गरफ्तार करने हेतु युद्धक वमिन को भेजा । पश्चिमी शक्तियों द्वारा इसकी "स्टेट पाइरेसी" (जसिमें राज्य शामिल है) के रूप में नदि की गई ।

### यूरोपीय संघ द्वारा उठाए गए कदम:

- **हवाई क्षेत्र पर प्रतर्बिध:**
  - बेलायूसी एयरलाइनों को EU के 27-राष्ट्र ब्लॉक के हवाई क्षेत्र से प्रतर्बिधति करने का आह्वान कया और यूरोपीय संघ-आधारति वाहकों से पूरव सोवयित गणराज्य के ऊपर से उड़ान भरने से बचने का आग्रह कया ।
- **ज़बरन वमिन रोकने की जाँच:**
  - EU के देश ऐसे बेलायूसी व्यक्तियों की सूची को वसितृत करने के लये सहमत हुए, जनिके यात्रा करने पर पहले ही प्रतर्बिध लगाया जा चुका है और अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन (ICAO) से बेलायूस की इस घटना की तत्काल जाँच करने का आग्रह कया ।
  - इसने हरिसत में लये गए पत्रकार की रहिाई की भी मांग की ।
- **व्यक्तियों और व्यवसायों पर प्रतर्बिध:**
  - अक्तूबर 2020 के बाद से यूरोपीय संघ उत्तरोत्तर यात्रा प्रतर्बिध और संपत्ति ज़ब्त करने जैसे उपायों के साथ अधकि से अधकि प्रमुख राजनीतिक हस्तियों को प्रतर्बिधति कर रहा है ।
  - हाल की घटना के संबंघ में EU ने 88 व्यक्तियों और सात संस्थाओं की अपनी प्रतर्बिध सूची में जोड़ने का नरिणय लया ।
- **बलियिन-यूरो आर्थिक पैकेज:**
  - यूरोपीय संघ बेलायूस को 3 बलियिन यूरो का नविश पैकेज देने को तैयार था जसि अब तब तक फ्रीज कया जाएगा जब तक कि देश लोकतांत्रिकि नहीं हो जाता ।

### नहितार्थ:

- बेलायूस यूरोप के भीतर एवं यूरोप और एशया के बीच मार्गों के उड़ान पथ पर स्थति है । बेलायूस को प्रतर्बिधति करने से इदानों में कमी आएगी और एयरलाइंस पर अतरिकित आर्थिक भर पड़ेगा ।
- बेलायूस को एयरलाइन्स से हर दिन 70,000 यूरो तक आय होती है, इस राशि से वंचति होने से असुवधि होगी लेकनि बेलायूस की अर्थव्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

### अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन संगठन:

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक वशिष एजेंसी है, जसि वर्ष 1944 में स्थापति कया गया था, जसिने शांतपूरण वैश्वकि हवाई नेवगिशन के लये मानकों और प्रक्रयाओं की नीव रखी ।
- दसिंबर 1944 में शकिागो में अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन को लेकर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कये गए थे ।
- इसने हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परविहन की अनुमति देने वाले मूल सदिधांतों की स्थापना की और ICAO के नरिमाण का भी नेतृत्व कया ।

### उद्देश्य:

- अंतर्राष्ट्रीय हवाई परविहन की योजना और वकिस को बढ़ावा देना ताकदिनुया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरकि उड्डयन के सुरक्षति और व्यवस्थति वकिस को सुनश्चिति कया जा सके ।

### सदस्य:

- भारत इसके 193 सदस्यों में शामिल है ।

### मुख्यालय:

- मॉट्रयिल, कनाडा

### आगे की राह:

- बेलायूस के राष्ट्रपति को एक वैध सरकार का गठन सुनश्चिति करना चाहये जो देश की महत्त्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सके ।
- उन्हें वपिक्ष से बात करनी चाहये और संकट के शांतपूरण समाधान हेतु बातचीत की पेशकश करनी होगी ।

